



भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

सकारात्मक साप्ताहिक हिन्दी अखबार



jagrukjanta.net

10 सितम्बर- 16 सितम्बर 2025

आश्विन, पक्ष - कृष्ण, तिथि - तृतीया, संवत् 2082

पृष्ठ : 8

जयपुर,

बुधवार वर्ष-11, अंक-28,

मूल्य ₹ 5/- वार्षिक मूल्य : ₹ 250/-

शिशु को ट्रॉली में पहुंचा कर माँ की गोद पर पिल्ला कर रहा कब्जा!

माँ की ममता भी अब समय के साथ अपना स्थान बदलने लगी है। तभी तो आज कई माताएं अपने शिशु को ट्रॉली गाड़ी में घुमाते हुए देखी जा सकती हैं।

जबकि कई माताओं की गोद में शिशु की जगह आकर्षक पिल्ला पहुंच गया है। हालांकि आज भी माँ की ममता तो वैसे ही जीवित है जैसे पहले थी। कुछ समय पहले तक माता अपने नौनिहाल को दो-चार घंटे भी अपने से दूर छोड़ देती थी तो उसका कलेजा मुंह को आता रहता था। और जैसे ही वह घर पहुंचती, अपने नवजात को दुलारती, उसे स्नेह से पुचकारती। माँ को देखते ही शिशु भी हँसता (माँ की गोद में जाने के लिए उतावला होता) था। सबसे पहले माँ अपने शिशु को अपना दूध पिलाने लगती थी बाकी सब काम बाद में। मगर आजकल बहुत सी महिलाओं को देखा जा सकता है कि वह अपने पति के साथ घूमने जाएंगी तो बच्चा या तो साथ चल रही आया की गोद में होगा या फिर ट्रॉली गाड़ी में दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर कई माताएं ऐसी होती हैं जिनकी गोद में एक आकर्षक सा छोटा सा पिल्ला होता है जिसे वह चूमते हुए दुलारते हुए 'मेला बच्चा, ओले, ओले' करते हुए चली जा रही होती है। क्या आज की माताओं में ये ट्रेंड फैशन बन गया है या फिर ममता ने स्थान बदल लिया है। माता की गोद से दूर घर में बच्चे को आया पालती है। आया ही उसे भोजन कराती है वहीं उसकी साफ-सफाई करती है और वह बच्चा उसी को अपनी माँ समझने लगता है। कई नौकरी पेशा महिलाएं जो परिवार से दूर पति के साथ अकेले रहती हैं, वह भी बच्चों को आया के भरोसे या फिर आजकल बन रहे शिशु केन्द्रों में छोड़कर चली जाती हैं। नौकरी से आने के बाद बच्चे को घर लाती हैं। जब शाम को पतिदेव के साथ घूमने जाएंगी तो बच्चा ट्रॉली गाड़ी में होगा। कई माताएं तो शारीरिक फीगर बिगड़ने के डर से शिशु को अपना दूध ही नहीं पिलाती हैं। वह ऊपर का दूध यानि डेयरी के दूध से ही पलकर बड़ा होता है। बड़ा होने पर कहीं कोई बात सामने आ जाए और सामने वाला कहे कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आ मैदान में। ऐसे में क्या कहा जाए। माँ-बाप दोनों ही बच्चे को अच्छी परवरिश के नाम पर दूसरों के सहारे छोड़कर पैसा कमाने चले जाते हैं। अंत में स्वयं माँ-बाप ही, उस शिशु से बड़े होते युवक को पढ़ाई के नाम पर विदेश भेज देते हैं। विदेश में जाने के बाद बच्चा विदेशी और माँ-बाप देशी रहकर अंत समय में अकेले ही रह जाते हैं। ना वो फीगर काम आता है और ना ही वो पिल्ला काम आता है, जिसे बच्चे की जगह गोदी में घुमाया जाता था। इसलिए माताओं को चाहिए कि वे पारंपारिक संस्कृति की आंधी में हमारे देश की संस्कृति और ममता को यूँ ही कुत्तो और आया में नहीं बाँटें। वरना ममता मर गई तो परिवार के नाम पर कुछ नहीं बचेगा।

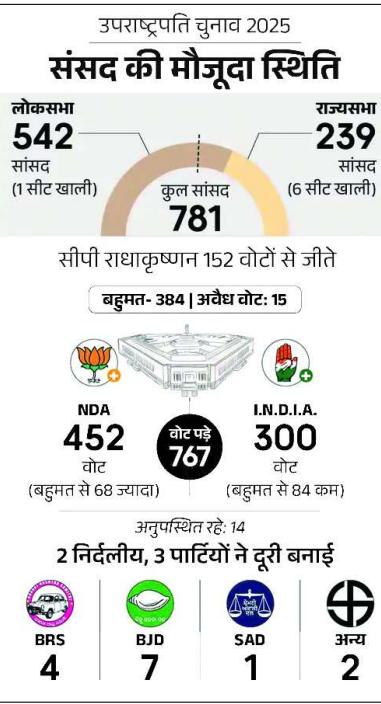
shivdayalmishra@gmail.com

सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति चुनाव में काँस वोटिंग, इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका, एनडीए को मिले उम्मीद से ज्यादा वोट

जागरूक जनता jagrukjanta.net

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले वहीं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। मतदान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। विपक्ष एकजुट है। उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है। उपर, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव में काँस वोटिंग हुई। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन के कम से कम 20 सांसदों ने काँस वोटिंग की



राज्य में रेलवे सुविधाओं का हो रहा निरंतर विस्तार आमजन को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हम संकल्पित-मुख्यमंत्री

जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। प्रदेश में मजबूत रेल नेटवर्क से आमजन को आवागमन में सुगमता होगी। साथ ही, स्थानीय रोजगार और उद्योगों को भी फायदा होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं के धरातल पर शीघ्र मूर्तरूप देने के लिए अधिकारी रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध टर्मिनल निर्माण से किसानों, औद्योगिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शर्मा



मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रत्नलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर में प्रस्तावित रेल टर्मिनल निर्माण से किसानों, औद्योगिक इकाइयों सहित सभी वर्गों को परिवहन

की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए संयुक्त निरीक्षण करें। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित राज्य सरकार तथा रेलवे के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वीसी के माध्यम से संबंधित जिलों के कलेक्टर भी जुड़े।

HBOT जीवन रक्षक प्रणाली द्वारा इलाज ऑक्सीजन (प्राणवायु) ट्रीटमेंट

- » मस्तिष्क चोट, पक्षाघात/लकवा
- » सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म
- » असाध्य घाव/शुगर के घाव
- » कैंसर (रेडियो थेरेपी) के साईड इफेक्ट
- » अचानक बहरापन (Hearing Loss)
- » डाईबेटिक फुट में अम्पुटेशन (पैर कटने) से बचाव

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
98290-17133, 70737-77133
9983317133
डॉ. हिमांशु अग्रवाल M.B.B.S. M.D.
नेशनल हायपरबैरिक रिसर्च सेंटर
594-B-C, जेम्स कॉलोनी, सैक्टर-3, मंदिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर
Dept. of Hyperbaric Medicine
Fortis Escorts Hospital
JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur
E-mail : hbotjaipur@gmail.com
www.nationalhbot.in

पंजाब बाढ़ राहत: पीएम मोदी ने की 1,600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने पंजाब की 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जो राज्य को पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भी उन्होंने 1,500 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब को SDRF (स्टेट डिजास्टर रिसर्पन्स फंड) की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को PM CARES for Children योजना के तहत दीर्घकालिक सहयोग मिलेगा।

नेपाल पीएम ओली का इस्तीफा, एयर इंडिया-इंडिगो की उड़ानें रद्द

नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं के निजी आवास पर हमला किया तथा संसद भवन में तोड़फोड़ की। छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में राजनीतिक वर्ग के खिलाफ कई कारणों को लेकर आम लोगों का बढ़ता आक्रोश झलक रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे शामिल हैं।

ओली ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा प्रदर्शनकारी कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद काठमांडू और अन्य स्थानों पर एकत्र हुए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए ओली के इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के उनके कार्यालय में घुसने और नाबंजी करने के तुरंत बाद ओली ने पद छोड़ दिया।

एअर इंडिया ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कीं भारत ने नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हवाई अड्डे के बंद होने की वजह से मंगलवार को दिल्ली से काठमांडू के बीच अपनी उड़ानें रद्द कर दीं। कंपनी ने एक बयान में बताया, 'काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरने वाली एआई2231/2232, एआई 2219/2220, एआई 217/218 और एआई 211/212 उड़ानें आज (मंगलवार) के लिए रद्द कर दी गईं।

PROPERTIES AUCTION
PAH
एस-11, द्वितीय तल, अपना बाजार, झोटवाड़ा, जयपुर
सेल, परचेज, रेंट एवं सैटलमेंट
ऑल इंडिया में प्रोपर्टी, सभी बैंकों से रिकवरी की गई प्रोपर्टी को उचित रेट में खरीदने व सैटलमेंट के लिए सम्पर्क करें।
ऑल इंडिया प्रोपर्टी के डॉक्यूमेंट लीगल चैक करने के लिए सम्पर्क करें।
सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट
सी.पी. अग्रवाल संस्थापक
मो.-8561088777

MADHAV UNIVERSITY
(Established by the Rajasthan State Govt. Legislature Act No. 67 of 2014)
Most Preferred University of Rajasthan
NAAC ACCREDITED
2025-26 ADMISSION OPEN

NURSING GME B.Sc. Nursing	LIBRARY (APPROVAL BY UGC & State Govt.) P. LIBRARY M. LIBRARY M. LIBRARY	ENGINEERING (APPROVAL BY UGC & State Govt.) Diploma (Civil, Mechanical, Electrical, ECE, CSE) B.Tech. CSE with Specialization (Artificial Intelligence, Embedded Systems, Cloud Computing, IoT, Blockchain, Big Data Analytics, Data Science, ML, AI, etc.)	PHYSICAL EDUCATION (APPROVAL BY NCRI) B.A. (PE) B.Ed. (PE) M.P.T. PGDPM
HOMEOPATHY (APPROVAL BY NCRI) B.A.M.S.	ARTS, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES (APPROVAL BY UGC & State Govt.) B.A. B.Com. M.A. M.Sc.	COMMERCE & MANAGEMENT (APPROVAL BY UGC & State Govt.) B.Com. M.Com. BBA MBA	PHARMACY (APPROVAL BY PCI) B.Pharm M.Pharm
YOGA & NATUROPATHY (APPROVAL BY UGC & State Govt.) B.Y.N. PGDPM PGDPM PGDPM	CLINICAL PSYCHOLOGY (APPROVAL BY NCRI) M.Sc. Psychology	COMPUTER SCIENCE & APPLICATIONS (APPROVAL BY UGC & State Govt.) Diploma B.Tech. MCA M.Sc. (IT) M.Sc. (AI)	LAW (APPROVAL BY NCRI) B.A. LL.B. LL.M. LL.M. (1 Year) LL.M. (2 Year)
PARAMEDICAL (APPROVAL BY NCRI) B.Sc. (Medical Laboratory Technology) B.Sc. (Medical Imaging Technology) B.Sc. (Medical Radiography) B.Sc. (Medical Sonography) B.Sc. (Medical Nutrition) B.Sc. (Medical Dietetics) B.Sc. (Medical Microbiology) B.Sc. (Medical Biochemistry) B.Sc. (Medical Pharmacology) B.Sc. (Medical Pathology) B.Sc. (Medical Forensic Science) B.Sc. (Medical Toxicology) B.Sc. (Medical Immunology) B.Sc. (Medical Hematology) B.Sc. (Medical Geriatrics) B.Sc. (Medical Palliative Care) B.Sc. (Medical End-of-Life Care) B.Sc. (Medical Reproductive Health) B.Sc. (Medical Maternal & Child Health) B.Sc. (Medical Public Health) B.Sc. (Medical Environmental Health) B.Sc. (Medical Occupational Health) B.Sc. (Medical Sports Science) B.Sc. (Medical Rehabilitation) B.Sc. (Medical Prosthetics) B.Sc. (Medical Orthotics) B.Sc. (Medical Assistive Technology) B.Sc. (Medical Assistive Devices) B.Sc. (Medical Assistive Services) B.Sc. (Medical Assistive Research) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assistive Entrepreneurship) B.Sc. (Medical Assistive Leadership) B.Sc. (Medical Assistive Management) B.Sc. (Medical Assistive Policy) B.Sc. (Medical Assistive Regulation) B.Sc. (Medical Assistive Standards) B.Sc. (Medical Assistive Quality) B.Sc. (Medical Assistive Ethics) B.Sc. (Medical Assistive Governance) B.Sc. (Medical Assistive Accountability) B.Sc. (Medical Assistive Transparency) B.Sc. (Medical Assistive Integrity) B.Sc. (Medical Assistive Honesty) B.Sc. (Medical Assistive Fairness) B.Sc. (Medical Assistive Justice) B.Sc. (Medical Assistive Equity) B.Sc. (Medical Assistive Inclusion) B.Sc. (Medical Assistive Diversity) B.Sc. (Medical Assistive Sustainability) B.Sc. (Medical Assistive Resilience) B.Sc. (Medical Assistive Adaptability) B.Sc. (Medical Assistive Flexibility) B.Sc. (Medical Assistive Creativity) B.Sc. (Medical Assistive Innovation) B.Sc. (Medical Assist			

जागरूक जनता
ऑन लाइन पढ़ने के लिए स्कैन करें



ई-पेपर व अन्य खबरें देखें
jagrukjanta.net

जागरूक खबरें
कॉन्स्टेबल भर्ती-2025:
एडमिट कार्ड 11 सितंबर से
होंगे डाउनलोड, जानें परीक्षा
से जुड़ी हर जरूरी बात

जयपुर @ जागरूक जनता। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा 13 सितम्बर को दूसरी पारी में और 14 सितंबर दोनों पारियों में आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदाभ्यर्थी बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभ्यर्थी 9 सितंबर से अपने परीक्षा केंद्र, जिले और पारी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। ई-प्रवेश पत्र 11 सितंबर 2025 से अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी राजकॉम के हेल्पलाइन नंबर 7340557555 या 9352323625 पर और विभाग के संपर्क नंबर 0141-2821597 या ईमेल igrecraj@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

राजस्थान में एक जनवरी 2024 से अब तक 42 नवीन न्यायालय खोले गए-पटेल

जयपुर @ जागरूक जनता। राजस्थान में एक जनवरी 2024 से अब तक 42 नवीन न्यायालय खोले गए हैं। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्नों का जवाब में यह जानकारी दी। पटेल ने कहा कि उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रदेश में नए न्यायालय खोले जाते हैं। उन्होंने सबको बताया कि वर्ष 2024 से अब तक प्रदेश में 42 नवीन न्यायालय खोले गए हैं।

राजस्थान वक्फ बोर्ड ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री

जयपुर @ जागरूक जनता। राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर की ओर से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मंगलवार को यहाँ राहत सामग्री रवाना की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक उफोक खान और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानु खान बुधवाली ने हरी झंडी दिखाकर इस राहत सामग्री का रवाना किया। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों का स्वभाव हमेशा से मदद करने का रहा है। चाहे उड़ीसा की बाढ़ हो, गुजरात का भूकंप, केदारनाथ त्रासदी या केरल की बाढ़ हर आपदा में राजस्थान के लोग आगे आए हैं। उड़ीसा बाढ़ के समय उस वक़्त श्री राज्यवासियों ने 20-25 करोड़ रुपये राहत कोष में दिए थे। गुजरात भूकंप के दौरान राजस्थान सरकार ने सैकड़ों टुक़ राहत सामग्री भेजकर हरसंभव मदद की थी।

स्वायत्त शासन विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

शहर चलो अभियान के संचालन के लिए प्रभावी कार्ययोजना करें तैयार-देबाशीष

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन और मंत्री झ़ाबर सिंह खर्वा के नेतृत्व में आमजन को सुगम जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्ठ और शासन सचिव रवि जैन द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्ठ ने सभी नगरीय विकास न्यास के सचिव को निर्देशित



करते हुए कहा की शहर चलो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करना सुनिश्चित करें, कैम्प से पूर्व रोड, सीवरेज प्रणाली, लो लेंडिंग एरिया आदि का सघन निरीक्षण कर जलभराव वाली जगहों पर मड पम्प के सहारे जलनिकासी की जाए, साथ ही कैम्प के अंतर्गत

अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर बनेगा अभियान

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने कहा की राज्य सरकार की मंशानुसार शहर चलो अभियान के माध्यम से लोग को लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य है, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाए। जैन ने कैम्प स्थल पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा की कैम्प स्थल के आसपास इस्टेबल अनिवार्य रूप से लगाए ताकि वहाँ कचरा न फैले। साथ ही उन्होंने कैम्प स्थल के पास वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए।

जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक कमजोर तबकों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण -गृह राज्य मंत्री

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पारित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेदूम ने कहा कि यह विधेयक प्रदेश में समरसता को बनाए रखने और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की सनातन संस्कृति हमेशा से उद्धार रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसमें धोखे, प्रलोभन, भय और छल कपट से धर्म परिवर्तन करवाने का कहीं भी समर्थन नहीं किया गया है।

सामूहिक धर्मांतरण एवं कमजोर तबकों का धर्मांतरण करने पर अब आजीवन कारावास

विधेयक के अनुसार छल कपट से धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। साथ ही, न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अल्प वयस्क, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आदि को कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने पर न्यूनतम 10 से लेकर 20 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। साथ ही, न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कपटपूर्ण तरीकों से सामूहिक धर्म परिवर्तन



करवाने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। साथ ही, उन पर न्यूनतम 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी एवं अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकेगा। साथ ही, न्यूनतम 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी व्यक्ति को जीवन, संपत्ति के लिए धमकाने वाले, झांसा देकर विवाह करने, बेचकर दुर्व्यापार करने या इस निमित्त दूषित करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 20 वर्ष लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। साथ ही, न्यूनतम 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पूर्व में दोषी सिद्ध हो चुके व्यक्ति को इसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम 20 वर्ष लेकर

आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। साथ ही, न्यूनतम 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, जिन संपत्तियों का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किया गया है उनकी जन्वी की जा सकेगी। विधेयक के अनुसार विधेयक के उद्देश्य से किया गया विवाह फैमिली कोर्ट या इस विधेयक में निर्धारित अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। नए विधेयक के अंतर्गत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से एवं बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन करने की जानकारी 90 दिन पहले देनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में न्यूनतम 7 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकेगी। साथ ही, न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्माचार्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष धर्म परिवर्तन का नोटिस 2 माह पहले देना होगा। उल्लंघन की स्थिति में न्यूनतम 10 से 14 वर्ष तक की सजा हो सकेगी तथा न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

जबरन धर्मांतरण समाज के लिए खतरा, लक्ष्य पर कमजोर तबके

बेदूम ने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन इसका सामाजिक अव्यवस्था फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है परंतु बलपूर्वक एवं प्रलोभन से धर्मांतरण करने का हक किसी को नहीं है। बेदूम ने कहा कि भारत के धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे धर्म की हानि होती हो। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से धोखे, छल कपट, प्रलोभन आदि से धर्मांतरण को निषेध किया गया है। समाज में शांति एवं सद्भाव बनाने के लिए यह एक उचित कदम है। बेदूम ने कहा कि सुनियोजित रूप से धर्मांतरण करने वाले लोगों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शोषितों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया जाता है।

न्यायालयों ने भी माना जबरन धर्मांतरण को गंभीर खतरा

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि धोखे से धर्म परिवर्तन करवाना पीड़ित व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। भारतीय न्यायालयों द्वारा अनेक अवसरों पर जबरन धर्मांतरण को गैर कानूनी माना गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार की अधिकार दिया गया है न कि जबरन धर्म परिवर्तन का। सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों के उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जबरन धर्मांतरण को एक अवैध गतिविधि और गंभीर खतरा बताया गया है। जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियाँ राष्ट्रीय अस्मिता के साथ-साथ सनातन संस्कृति के लिए हानिकारक है।

धर्मांतरण विरोधी कानून विभिन्न राज्यों में लागू, प्रदेश सरकार जबरन धर्मांतरण पर सख्त

बेदूम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 1978, आंध्र प्रदेश में 2007, उत्तराखंड में 2018, हिमाचल प्रदेश में 2019, उत्तर प्रदेश में 2021, कर्नाटक में 2021 और हरियाणा में 2022 में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू आ चुके हैं। राजस्थान में भी तत्कालीन सरकार द्वारा 2008 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जबरन धर्मांतरण पर पूर्णतया लगाम लगाने हेतु सख्त कानून प्रदेश की विधानसभा में लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस विधेयक को विधानसभा में रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन न कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की है। इस तरह के मामले अलवर, बांसवाड़ा आदि जिलों में सामने आने पर अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में द्रव्यगुणोदीयमानम् विषय पर 6 दिवसीय सीएमई कार्यक्रम शुरू

15 राज्यों के 30 प्रतिभागी करेंगे द्रव्यगुण के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर चर्चा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में द्रव्यगुण विभाग द्वारा "द्रव्यगुणोदीयमानम्" विषय पर 6 दिवसीय सीएमई कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आयुष आहार समिति की अध्यक्ष एवं पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मीता कोटेचा ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. कोटेचा ने कहा कि "आयुर्वेद में औषध द्रव्यों की तरह आहार द्रव्यों का मानकीकरण भी आज की आवश्यकता बन गया है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आयुष आहार नियमावली 2022 का प्रकाशन किया गया है।"

इस अवसर पर द्रव्यगुण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुदीप रथ ने सीएमई के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य औषधियों



की गुणवत्ता एवं कार्यमुक्ता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करना है। इस हेतु प्रतिभागियों को एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, एलसी-एमएस, आईसीपी-एमएस, जीसी-एमएस, माइक्रो सिटी, एवं एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन जैसे आधुनिक उपकरणों और विधियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रो. सुदीप रथ ने बताया

कि इस सीएमई में भारतवर्ष के 15 राज्यों से कुल 30 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में संस्थान के समस्त शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं एवं शोधार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम आगामी दिनों में विविध तकनीकी सत्रों और प्रायोगिक कार्यशालाओं के माध्यम से द्रव्यगुण विषय को आधुनिक संदर्भों में सुदृढ़ करेगा।

धमाकेदार मानूसन की प्रदेश से धीमे पाव विदाई!

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान में आज से आगामी एक सप्ताह तक भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में मानसून की संभवतया विदाई माना जा रहा है। चूंकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, प्रदेश में आज से ही

भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने व 11 सितंबर से अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। आगामी दो से तीन दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढोत्तरी हो सकेगी।

चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी परीक्षा राज्य में निष्पक्षता से संपन्न करावेंगे

जयपुर @ जागरूक जनता। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि 19 से 21 सितम्बर तक राज्य के 38 जिलों में आयोजित होने वाली चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी परीक्षा निष्पक्षता से संपन्न करवाई जायेगी। परीक्षा तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को बीकानेर और राज ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि इस परीक्षा में करीब 25 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे।

INDIA'S NO.1 SCHOOL MANAGEMENT ERP & MOBILE APPS

JUST ₹10*

LIMITED TIME OFFER

ERP FEATURES

- Reception
- Students
- Fees
- Exam
- Transport
- Accounts
- Hostel
- Admin
- Library
- Stock
- Staff
- Timetable

MOBILE APP

- Admin App
- Principal App
- Coordinator App
- Teachers App
- Students App
- Driver App

15 YEARS

TRUSTED SELLER

+91 9694-222-788

Schedule a Free Demo Now

www.paaathshalaerp.com

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म चिकित्सा एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर केन्द्रित 6 दिवसीय सीएमई का समापन

पंचकर्म चिकित्सा और महिला स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव-अनुसंधान

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईएर), मानंद विद्यापीठालय, जयपुर के प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विभाग आयुर्वेद पंचकर्म विभाग की ओर से आयोजित छह दिवसीय सीएआईए का समापन शनिवार, 6 सितंबर को हुआ। यह कार्यक्रम सितंबर के 6 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के कुपनती प्रो. सज्जिका शर्मा ने की। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सहयोग से किया गया। इस सीएआईए में देशभर से आयुर्वेद विशेषज्ञ, शिक्षक, चिकित्सक एवं शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पंचकर्म चिकित्सा और मिलातीओं के स्वास्थ्य से जुड़े विविध विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और अनुशुद्धिजन प्रस्तुत किए। पंचकर्म विभाग की ओर से आयोजित सीएआईए में कई रोगों में पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की गई।

पंचकर्म विभागाध्यक्ष प्रो. गोपेश मंगल ने बताया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग की ओर से आयोजित इस 6 दिवसीय



प्रशिक्षण कार्यक्रम ने चिकित्सकों को पंचकर्म प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान की है। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने की।

जिसमें पंचमर्म की परिभाषा, प्रासंगिकता तथा वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य स्नेह, अभ्यंतर स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन, बरती, नख तथा रक्तेन्द्रोक्षण जैसी प्रमुख पंचमर्म प्रक्रियाओं पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत व्याख्यान, व्यावहारिक प्रदर्शन एवं समझ-चर्चा आयोजित की गई। 6 दिवसीय CME में प्रो. यू.एस. निगम, डॉ. जितेन्द्र शर्मा, डॉ. मयंक भट्टराठी, डॉ. ज्ञान प्रकाश समल, डॉ. सर्वेश्वर कुमार सिंह, प्रो. जे.पी. सिंह, डॉ. ऋजु अग्रवाल,

डॉ. अभिषेक भट्टाचार्य, प्रो. गोपेश मंगल, डॉ. अनिल भारद्वाज, डॉ. प्रवीन के. मडिकोंडा एवं प्रो. सुमन शर्मा जैसे पंचकर्म विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और शोध साझा किए। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से आयोजित सीएमई में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित रोगों के आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से रोग निदान पर चर्चा की गई।

प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. भारती कुमारमंगलम ने बताया प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से आयोजित इस 6 दिवसीय सीएमई में AIIA (ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली), ITRA (इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद), जामनगर, तथा BHU

(काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी) जैसे गतिशील संस्थानों के विरुद्ध विख्याताओं ने गतिशील परिचयों, प्रसव विज्ञान एवं स्त्री रोगों पर अपने व्याख्यान दिए। विशेषज्ञों ने आयुर्वेद की नवीनतम चिकित्सा विधियों, अनुसंधान की दिशा में हो रहे नवाचारों और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही, विशिष्ट राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और पारस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया। प्रतिभागियों को विशिष्ट स्त्री रोगों की आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रबंधन, मॉक ड्रिल तथा हेन्ड्स-ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया।



जागरूक **जनता** नेटवर्क
jagrukjanta.net

चितौड़गढ़। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौड़गढ़ एवं नौसेल अधिकारी राष्ठीय तंबाकू नियंत्रण प्रकांड (एन्टीस्मोर्) एवं विकल्प इंडिया सोसाइटी जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में चितौड़गढ़ जिले के ब्लॉक राष्मी, गंगार, निवाहेड़ा, कापान, भूपालसागर, भदसर, डुंगला, चितौड़गढ़, बरसोदेडी, बेगू, रावगभटा क्षेत्र में निजी एवं राजकीय विद्यालयों में राष्ठीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू मुक्त विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को तंबाकू व धूम्रपान से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी तथा तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के विषय में स्लाइड प्रजेंटेशन से अवगत कराया जा रहा है जिले के विद्यालयों में सोसायटी द्वारा बैनर,

पलेट वितरण एवं चस्पा कर शिक्षण परिसर में 100 हजार की परिधि क्षेत्र में तंबाकू विक्रेता एवं सेवन को कानूनी अपराध मानते हुए 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान हेतु बताया जा रहा है व विद्यालयों में तंबाकू मुक्त समितियां बनवाई जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ निबंध प्रतियोगिता एवं तंबाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई जा रही है। सोसायटी के अध्यक्ष संजय कटार द्वारा बताया गया क्षेत्र में सोसाइटी के प्रतिनिधि बतौर गोवर्ध मिश्रा, प्रेम प्रकाश एवम पुरुषोत्तम शर्मा उक्त कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में प्रमाण पत्र और का वितरण किया गया। कार्यक्रम आयोजन के दौरान ही सोसाइटी प्रतिनिधियों द्वारा कोटप्पा अर्धनियमन 2003 के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के आयोजन में बच्चों व शिक्षकों ने बड़ चक्कर कर हिस्सा लिया।

**माधव विश्वविद्यालय में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का
आगाज: छह दिन तक होंगे जागरूकता कार्यक्रम**

आबूरोड @ जागरूक जनता माधव विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी संकाय ने विद्यार्थियों के फिजियोथेरेपी दिवस 2025 का शुभारंभ हुआ। वैश्विक थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था: वृद्धों में कमजोरी और गिरने से बचाव" को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उद्घाटन समारोह में केक काटने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को लेकर छह दिन तक यहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की गतिशीलता, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में विशेषज्ञ व्याख्याता, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, समुदायिक कार्याशालाएँ

जागरूकता रैली, पोस्टर प्रदर्शनी और फिजियोथेरेपी तकनीकी का प्रदर्शनी शामिल रहेगा। समापन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के चांसलर हिमालसिंह देवल ने कहा कि फिजियोथेरेपी केवल उपचार का साधन नहीं, बल्कि सुस्थित और सम्मानजनक वृद्धावस्था की कुंजी है। प्रिंसिपेंट डॉ. राजीव माथुर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज का अनुभव भण्डार हैं और उनके लिए सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देना हम सबको जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रार डॉ. भावेश कुमार ने कहा कि माधव विश्वविद्यालय हमेशा समाज हितों की पहल करता आया है व भविष्य में भी करता रहेगा।

विभागीय अधिकारी नियमित फील्ड में दौरा कर आमजन को राहत पहुंचाएं-आक्या

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

चिन्तौड़गढ़। बारीश के मौसम में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो ऐसे में विभागीय अधिकारी नियमित फील्ड में दौरा कर रहत पहुचाने का कार्य करे। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या शनिवार को पंचायत समिति के सभागार में राज्य सरकार के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के समस्त विभागीय के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बरसात के मौसम को देखते हुए आमजन को किसी प्रकारी की असुविधा न हो इस हेतु सभी विभाग अपने से संबंधित कार्य को आवश्यकता अनुसार तुरंत पूरा करे। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से शहर व गांवों में बिजली आपूर्ति निबंध रूप से मिलती रहे यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा की ग्रामफोन कार् अतिरिक्त स्टॉक रखा जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क व पुलिया की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को



दिये। विधायक आक्या ने बैठककरने के दौरान पंचायत समिति की कार्य समस्त ग्राम पंचायतो में विभिन्न प्रश्नों में संचालित कार्यों को दो माहामें पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध कब्जे नहीं होने देने संबंधी ग्रामा विकास अधिकारियों को निर्देश करने देते हुए नियमानुसार पट्टे जारी व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से मरम्मत योग्य व जरूरत हो चुके विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को न बिठाने व साधनानी बरतने के निर्देश देते हुए ऐसे विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची अविलम्ब उच्चाधिकारियों प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने डीएमएफटी फण्ड से राउमावि में दो दो कक्षा कक्ष निर्माण की जानकारी देते हुए विद्यालयों में नए कक्षा कक्ष प्रस्ताव, मरम्मत के प्रस्ताव

भजवाने के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये। विधायक आक्या ने विजयपुर, बड़ोदिया, रोलाहेड़ा में पेयजल सप्लाई तीन-तीन दिवस में मात्र आधे घण्टा सप्लाई होने पर नाराजी जाहिर करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को पेयजल सप्लाई निर्बाध रूप से कराने के निर्देश दिये। साथ ही बरसात मौसम के पश्चात समस्त खराब हो चुके हैंडपंप को तुरन्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ब्लॉक मुख्याधिकारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से उपकेंद्रे, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिकार्डों की जानकारी लेते हुए क्षतिग्रस्त भवनों की सूची उच्चाधिकारियों को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने बस्सी अस्पताल के नवीन भवन निर्माण एवं प्रस्तावित सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये।

**जन-जागरूकता ही बाल
विवाह रोकने का सबसे
बड़ा साधन - जिला
कलक्टर आलोक रंजन**

चिन्तौड़गढ़ @ जागरूक

चितौड़गढ़ @ जागरूक जनता। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए सबसे अहम हथियार जन-जागरूकता है। इसके लिए प्रतिबंध अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधान समझाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और संगठनों से बाल विवाह मुक्त राजस्थान की मुद्रिम में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जिला कलक्टर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यशाला-समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी बाल विवाह जानकारी जुटाएं और बाल विवाह की आशंका होते ही तुरंत रोकथाम करें। अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) प्रभा गौतम ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल पर अधिकारियों की कार्यप्रगति की मॉनिटरिंग होगी। सह. निदेशक बाल अधिकारिता अमनप्रकाश तोषनीवाल ने अधिनियम प्रावधानों के बारे में बताया। बैठक में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, सामाजिक न्याय चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षक दिवस

26 शिक्षकों को मिला टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

भीलवाड़ा। शिक्षक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित द ग्लोरी अवार्ड्स समारोह में 26 शिक्षकों को टीचिंग एक्सेल्लेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीख कोसाइडटी और टिल्स एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए आयोजन में सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को शुरुआत समूह चर्चा से हुई। वरिष्ठ शिक्षकों ने अपने लंबे अनुभव का काला काल कहें कि शिक्षक केवल पेशा नहीं बल्कि जीवन मूल्यों को सँवरने का



माध्यम है। नए शिक्षकों ने भी अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और बताया कि एक शिक्षक को हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बने

रहना चाहिए। इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों में राज सिंह भाटी, अजय चौधरी, ईशा शर्मा, रेखा तेली, लक्षिता शर्मा, पायल लोढ़ा, सुमन भगत, मीनाज

खान, अनुकृति माधुर, यशु
कुशवाह, मुस्कान जैन, मोहम्मद
संदिल रांगज, मोनिका शुक्ला,
वंदना लुधानी, अभिषेक ठठेरा,
वंदना डड, चंदा तेली, सिया
आहुजा, गोपाल प्रजापत, सरोज
वैजवा, प्रवीणधर तेली, दिव्यांशु
शुक्ला, मुरली सिंह, पलक
गोखरू, नीलकमल खराडी और
अश्वय जोशी शामिल रहे। अंत में
सह-निदेशक अभिराधा मोदी ने
सभी शिक्षकों का धन्यवाद करते
हुए कहा कि इस प्रकार के
आयोजन शिक्षकों को
आत्ममंथन का अवसर प्रदान
करते हैं और शिक्षा के स्तर को
ऊँचाई तक ले जाने में सहायक
सिद्ध होते हैं।

जागरूक जनता

www.jagrukjanta.net
विश्वसनीय समाचार पत्र

जी हॉ, यदि आपको अपने प्रतिष्ठान का व्यापार का विज्ञापन देना है तो जागरूक जनता समाचार पत्र द्वारा पूरे राजस्थान के साथ-साथ 4 अन्य राज्यों में आपका विज्ञापन प्रसारित किया जायेगा।

जो दिखेगा वही बिकेगा

आज ही बुक करें विज्ञापन









आपके व्यापार की तरक्की

जागरूक जनता के साथ

विज्ञापन

क्लासीफाइड

डिस्पले

प्रॉपर्टी

वैवाहिक

विज्ञापन बुक करें: 9928022718 9829329070

